

अपील भरण पोषण संख्या 11/2016 अनवानी स्नेहलता पत्नि तिलकराज
जाति अरोडा निवासी 1/365 हाउसिंग बोर्ड श्यामनगर पुरानी आबादी
श्रीगंगानगर बनाम 1-रोहित पुत्र तिलकराज जाति अरोडा निवासी 1/365
हाउसिंग बोर्ड, श्यामनगर, पुरानी आबादी श्रीगंगानगर 2-नीरू पत्नि रोहित
पुत्र तिलकराज जाति अरोडा निवासी 1/365 हाउसिंग बोर्ड श्यामनगर
पुरानी आबादी श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

06-02-2017

अपीलार्थीया स्नेहलता व रेस्पोजेन्टस रोहित व नीरू उपस्थित है।
दोनो पक्षो की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया
गया।

अपीलार्थीया स्नेहलता का कथन था कि उसके द्वारा उपखण्ड
मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 28.06.2016 को एक प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 23 माता पिता व वरिष्ठ नागरिक का कल्याण अधिनियम 2007
के अन्तर्गत पेश किया था कि वह 60 साल की वृद्ध एवं वरिष्ठ नागरिक है
और उसने जरिये ईकरारनामा दिनांक 30.04.96 को एक मकान न. 1/365
हाउसिंग बोर्ड श्यामनगर पुरानी आबादी श्रीगंगानगर पैमायशी 6 इन्टू 11.25
मीटर उतर दिशा में खुलता हुआ है जो उसका कय शुदा है जो कि तीन
कमरो का बना हुआ है। जिस पर खरीद की दिनांक से ही वह काबिज चली
आ रही है। उसका कथन था कि रेस्पोजेन्टस सं० 1-रोहित, जो कि अपीलार्थीया
का पुत्र है और रेस्पोजेन्टस सं० 2-नीरू उसकी पुत्रवधु है दोनो मिलकर उसका
मकान हड़पना चाहते है और दो माह पूर्व मकान पर उनके द्वारा जबरन
कब्जा कर लिया है और मकान अपने नाम करवाने के लिए रेस्पोजेन्टस उसके
विरुद्ध झूठे मुकदमें करवाते रहते है और मारपीट करते है। इसलिए उसका
प्रा० पत्र स्वीकार कर रेस्पोजेन्टस (अप्रार्थीगण) को बेदखल किया जाकर उसे
कब्जा दिलाया जावे।

उसका आगे कथन था कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर ने उसका
प्रा० पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया है कि वह 50 वर्ष की है और
वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में नहीं आती है जबकि माता पिता के लिए वरिष्ठ
नागरिक होना आवश्यक नहीं है। माता पिता अपनी संतान से अपना भरण
पोषण और अपनी सम्पत्ति के संबंध में कार्यवाही कर सकती है। उक्त
विवादित मकान उसका कय शुदा है। इसलिए उसकी अपील स्वीकार की
जावे और उपखण्ड मजि० श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 04.08.2016 निरस्त
किया जावे और मकान खाली करवाया जाकर कब्जा उसे दिलवाया जावे।

इसके विपरीत रेस्पोजेन्टस रोहित व नीरू की ओर से कथन था कि
रेस्पोजेन्टस सं० 2 नीरू पुत्रवधु है और उक्त माता पिता व वरिष्ठ नागरिक का
कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की
जा सकती। उनका आगे कथन था कि अपीलार्थीया 50 वर्ष की है और वह
वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में नहीं आती है और वह आरकेस्ट्रा का कार्य करती
है जिससे उसे 50 हजार रुपये प्रतिमाह आमदनी होती है और उसके पास
यूनियन बैंक में 10 लाख की एफडीआर भी है उसे किसी प्रकार के भरण
पोषण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उपखण्ड मजि० श्रीगंगानगर द्वारा
उसका प्रा० पत्र सही रूप से खारिज किया गया है।

बालाजी
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनके आगे यह भी कथन था कि अपीलार्थीया के पास बटिण्डा, मलोट व चण्डीगढ में भी एक एक मकान है। उसके द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की गयी है जो खारिज की जावे। उनका यह भी कथन था कि विवादग्रस्त मकान रेस्पो० सं० 1-रोहित के दादा ने अपीलार्थीया को खरीद कर दिया था, जो जदी जायदाद है और रेस्पो० सं० 1 का उक्त मकान में जन्म से ही हिस्सा है और वह जन्म से ही उक्त मकान में रहता आ रहा है और विवाह के बाद अपनी पत्नि नीरू के साथ उक्त मकान में ही निवास करता आ रहा है। अपीलार्थीया जान बूझकर उन्हें परेशान करती है और झूठी दरखास्ते पेश करती रहती है और उनके विरुद्ध झूठे मुकदमें दर्ज करवाती रहती है। इसलिए अपीलार्थीया की अपील खारिज की जावे।

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजि० (भरण पोषण अधिकरण) श्रीगंगानगर के समक्ष अपीलार्थीया ने दिनांक 28.06.2016 को एक प्रा० पत्र माता पिता व वरिष्ठ नागरिक का कल्याण अधिनियम 2007 धारा 23 के तहत इस आशय का पेश किया कि वह 60 वर्ष की एक वृद्ध एवं वरिष्ठ नागरिक है और उसके नाम से दिनांक 30.04.96 के ईकरारनामा के द्वारा ओमप्रकाश पुत्र टालाराम डोडा से मकान न० 1/365 हाउसिंग बोर्ड, श्याम नगर, पुरानी आबादी श्रीगंगानगर का पैमायशी 6 इन्टू 11.25 मीटर उतर दिशा में खुलता हुआ क्वथ शुदा है जिस पर रेस्पोडेन्टस उसके पुत्र रोहित व पुत्रवधु नीरू मकान को हडपना चाहते हैं और दो माह पूर्व उन्होंने कब्जा कर लिया है और आगे उसे बेच देंगे। इसलिए उसका प्रा० पत्र स्वीकार किया जावे और मकान का कब्जा पुलिस सहायता से दिलाया जावे। उपखण्ड मजि० श्रीगंगानगर द्वारा दोनो पक्षो को सुनने के पश्चात दिनांक 04.08.2016 को निम्न आदेश पारित किया गया:-

हमने प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थनापत्र मय सलंगन दस्तावेजात एवं अप्रार्थीगण के जबाब का अवलोकन किया। अप्रार्थीयान की ओर से प्रार्थीया की उम्र के बारे में जो दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये हैं, के अनुसार प्रार्थीया की उम्र 50 वर्ष ही है जो वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में नहीं आती है। प्रार्थीया अप्रार्थी सं० 2 पुत्रवधु से भरणपोषण के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं कर सकती है। वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007 की धारा 5 के अन्तर्गत प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र में चाही गई अनुतोष प्रार्थीया के दस्तावेज सक्षम नहीं होने के कारण दिया जाना संभव नहीं है। इसलिए प्रा० पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीया मकान खाली करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर सकती है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।

अपीलार्थीया ने अधिनस्थ न्यायालय में उक्त अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 28.06.2016 अपने मकान न. 1/365 हाउसिंग बोर्ड, श्यामनगर, पुरानी आबादी श्रीगंगानगर पैमायशी 6 इन्टू 11.25 मीटर पर अप्रार्थीगण के अनाधिकृत कब्जा छुडवाकर वापिस दिलवाने की प्रार्थना के साथ पेश किया था।

माता पिता व वरिष्ठ नागरिक का कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 निम्न प्रकार से है:-

23. कुछ परिस्थितियों में सम्पत्ति का अन्तरण शून्य होगा:- (1) जहां किसी वरिष्ठ नागरिक ने, जिसने इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पत्ति का अन्तरण इस शर्त के अधीन किया है कि अन्तरिती अन्तरक को मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा और ऐसा अन्तरिती ऐसी सुविधाओं और शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने से इन्कार करता है या असफल रहता है, वहां सम्पत्ति इस प्रकार उक्त अन्तरण कपट या प्रपीड़न द्वारा या असभयक असर के अधीन किया गया माना जाएगा और अन्तरक की वांछा पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जायेगा।

उक्त धारा के अन्तर्गत राहत प्राप्त करने के लिए आवेदक वरिष्ठ नागरिक हो और उसके द्वारा उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पत्ति का इस शर्त के अधीन अन्तरण किया हो कि अन्तरिती अन्तरक को मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा।

इस मामले में यह देखा जाना आवश्यक है कि क्या अपीलार्थीया उक्त अधिनियम 2007 के अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आती है अथवा नहीं? यदि वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आती है तो क्या वह रेस्पोजेन्टस के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। इस संबंध में अधिनियम में दी गई वरिष्ठ नागरिक/माता-पिता व संतान की परिभाषा पर विचार करना आवश्यक होगा:-

धारा 2(ज) "वरिष्ठ नागरिक" से ऐसा व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है और जिसने साठ वर्ष या अधिक की आयु प्राप्त कर लिया है अभिप्रेत है।

धारा 2(छ) "सम्बन्धी" से अभिप्रेत है सन्तानहीन वरिष्ठ नागरिक का कोई विधिक उत्तराधिकारी, जो अवयस्क नहीं है और उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी सम्पत्ति का कब्जाधारी में है या को उत्तराधिकार में प्राप्त करेगा।

धारा 2(घ) "माता-पिता" से ऐसे माता या पिता अभिप्रेत है, जो जैविक, दत्कग्राही या सौतेला पिता या सौतेली माता, यथास्थिति, हों, चाहे पिता या माता वरिष्ठ नागरिक है या नहीं।

धारा 2(क) "सन्तान" के अन्तर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री सम्मिलित है किन्तु अव्यस्क सम्मिलित नहीं है।

चूंकि हस्तगत प्रकरण में स्नेहलता ने माता के रूप में धारा 23 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अपने पुत्र अप्रार्थी सं० 1-रोहित व अप्रार्थी सं० 2-नीरु पुत्र वधु के विरुद्ध अपने उक्त मकान का कब्जा प्राप्त करने के लिए पेश किया था जिसमें अपीलार्थीया की आयु 60 वर्ष से कम अर्थात् 50 वर्ष की मानकर उसे वरिष्ठ नागरिक न मानकर उसका प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो अधिनियम की धारा 2(घ) के विपरीत है। उक्त धारा के तहत माता पिता के लिए आयु 60 साल की होना आवश्यक नहीं है। इसलिए उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर का यह निष्कर्ष कि अपीलार्थीया वरिष्ठ नागरिक नहीं है, सही नहीं है।


जहां तक अप्रार्थी सं० 2-नीरू पुत्रवधु के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न है अधिनियम के अन्तर्गत माता पिता अपनी संतान के विरुद्ध ही कार्यवाही करने के लिए सक्षम है। धारा 2(क) में संतान की दी गई परिभाषा के अनुसार पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री सम्मिलित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संतान की परिभाषा में पुत्रवधु सम्मिलित नहीं है। इसलिए अप्रार्थी/रेस्पो० सं० 2 नीरू पुत्रवधु के विरुद्ध इस अधिनियम के तहत कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 सीआर.एल. आर. (एससी) पेज 726 स्टेट ऑफ बिहार आदि बनाम अरविन्द्र कुमार वगैरा के पैरा 13 में निम्न प्रकार से निर्देश दिये गये हैं:-

13. In Manish Goel Vs. Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099, this Courts has held that generally, no Courts has competence to issue a direction contrary to law nor the Court can direct an authority to act in contravention of the statutory provisions. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [See also- Vice Chancellor, University of Allahabad & Ors. Vs. Dr. Anand prakash Mishra & Ors. (1997) 10 SCC: and Karnataka State Road Transport Corporations Vs. Ashrafulla Khan & Ors.; AIR 2002 SC 629].

चूंकि रेस्पो० सं० 2-नीरू जो कि पुत्रवधु है और वह उक्त अधिनियम 2007 में दी गई संतान की परिभाषा में नहीं आती है, के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त में दिये गये मार्गदर्शन के अनुसार भी किसी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत कोई आदेश नहीं दिये जा सकते। इसलिए अपीलार्थीया, रेस्पो० सं० 2-नीरू पुत्रवधु के विरुद्ध उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही करने के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए संतान की परिभाषा के तहत केवल अप्रार्थी/रेस्पो० 1-रोहित पुत्र के विरुद्ध ही कार्यवाही की जा सकती है। इसलिए अपीलार्थीया की अपील अप्रार्थी/रेस्पो० सं० 1 रोहित के विरुद्ध ही आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीया की अपील रेस्पो० सं०-1 रोहित के विरुद्ध आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपजिला मजि० श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.08.2016 निरस्त किया जाता है और प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उक्त किये गये विवेचन को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 23 पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही अप्रार्थी सं० 1-रोहित की हद तक पुनः विचार कर और अप्रार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर पुनः निर्णय पारित किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रति सहित पालना के लिए वापिस लौटाया जावे। आदेश की एक एक प्रति अपीलार्थीया व रेस्पोडेन्टस को भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(ज्ञाना राम)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

434-437
21/02/2017